Selection of Site for Narora Atomic Plant

2368. SHRI RAOOF VALIULLAH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the site selected for Narora Atomic Plant was wrong and whether the same is in cosmic zone;

(b) whether the people of Bulandshahr in U.P. demonstrated for the plant's closure and have the employees voiced concern of the plant going critical this year;

(c) what was the report of the Vengurlaker site selection committee and the results of geological tests carried out at the site; and

(d) what is the total investment in the NAPP so far and whether adequate precautions have been taken to prevent radiation leaks and if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF OCEAN DEVELOPMENT, ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS AND SPACE (SHRI K. R. NARAYANAN): (a) No, Sir. Narora is a site suitable for locating an Atomic Power Station though it is in the seismic zone.

(b) Some section of population around the project have demanded closure of this Plant. The employees have not voiced any concern on the Plant going critical this year.

(c) Vengurlakar Committee recommended siting of Atomic Power Station at Narora which is specially designed to take into account the results of geological tests carried out at the site.

(d) Total investment in Narora Atomic Power Plant till January 1988 is approximately Rs. 450.90 crores. Adequate measures are inbuilt in the design of the NAPP to prevent radiation leaks.

हिन्दी तथा अंग्रेजी टंककों और आशुलिपिकों का चयन

2369. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न मंत्रालय और विभाग संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भरी जाने वाली अपनी रिक्तियों की मांग कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेज देते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह मांग राजभाषा अधिनियम के उपबन्धों के अधीन विभिन्न क्षेत्रों के लिए निश्चित किए गए कोटे के अनुसार भेजी जाती है; और

(ग) यदि हां, तो उपयुक्त आयोगों द्वारा 1984 से 1986 तक की अवधि के दौरान चयन किए गए हिन्दी और अंग्रेजी के टंककों और आशुलिपिकों की अलग-अलग संख्या कितनी है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जहां तक आशुलिपिकों का संबंध है, ये रिक्तियां केन्द्रीय सचिवालय योजना में शामिल मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय को सूचित की जाती है । उक्त योजना के अन्तर्गत न आने वाले पदों की रिक्तियां संबंधित मंत्रालयो/विभागो द्वारा सीधे ही संघ लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन आयोग को सूचित कर दी जाती है ।

(ख) राजभाषा अधिनियम में भर्ती के मामले में भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए कोटे का निर्धारण किए जाने का कोई प्रावधान नही हैं ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता । फिर भी संघ लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किए गए आशुलिपिकों के चयन में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों प्रकार के आशुलिपिकों को इस आधार पर कि वे किस भाषा की परीक्षा में बैठे थे, एक ही योग्यताक्रम सूची में शामिल किया जाता है ।

Diplomats Involved in Smuggling Activities

2370. SHRI BHAGATRAM MANHAR:
SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH:
SHRI JAGADISH JANI:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large number of Diplomats have been asked to leave the country for their alleged involvement in smuggling;

(b) if so, what are the details in this regard;

(c) whether it is also a fact that Government have arrested a large number of Indian nationals also who have been involved in smuggling activities and have been helping the foreign diplomats; and

(d) if so, what action has been taken against the guilty?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI K. NATWAR SINGH): (a) and (b) No, Sir. There have been only a few cases where discrepencies were noticed in the items declared and the items actually imported by diplomats. In such cases, the Ministry took stern action including confiscation of contraband goods and the offending diplomats were asked to leave the country.

(c) and (d) The information is being collected by the investigating agencies and the factual information will be placed on the Table of the House as soon as it is made available to us.

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

2371. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा मंत्रालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की संख्या कितनी है और उनमें से ऐसी समितियों की संख्या कितनी है जिन्होंने प्रत्येक वर्ष में चार बैठकें आयोजित की तथा उन गैर-सरकारी सदस्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने सदस्य अथवा पर्यवेक्षक के रूप में इन बैठकों में भाग लिया;

(ख) क्या हिन्दी के प्रसार में अत्यन्त कमी आई है और स्थिति यह है कि राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष और सदस्य यह नहीं बताते हैं कि उन्होंने कितना प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार सभी क्षेत्रों में सभी स्तरों पर हिन्दी का प्रयोग अनिवार्य बनाने का विचार रखती है ताकि सेना के सभी पक्षों में आत्म-सम्मान और आत्म-गौरव जगाया जा सके ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) रक्षा मंत्रालय की एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति है । वर्ष 1987 के दौरान इसकी चार बैठकें हुई । मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों में से एक सदस्य को इस समिति की बठकों में प्रेक्षक के रूप में आमंत्रित किया जाता है। हिन्दी सलाहकार समिति के एक सदस्य डा० वी० एन० किलिप ने मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 5 अक्तूबर, 1987 को आयोजित बैठक में प्रेक्षक के रूप में भाग लिया था। 25 या उससे अधिक अफसरों और कर्मचारियों वाले सभी कार्यालयों/यूनिटों आदि को अपने यहां राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित करने और नियमित रूप से उनकी तिमाही बैठकें आयोजित करने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं। चूंकि रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यालयों/